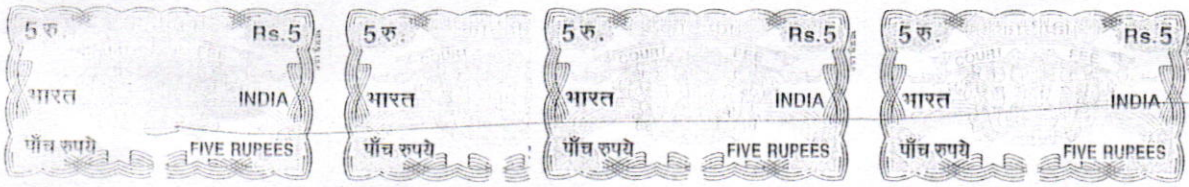


82

न्यायालय श्रीमान मामुनीय राजस्व मंडल म०प्र० ग वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



R 5527-16

रामसुमिरम साह पत्नी रामसुरत साह निवासी माडौर तहसील जवा जिला रीवा म०प्र०  
 विजारी वा म०प्र०

वनाम

1- श्रीमती सुमती पत्नी रामसुख साह निवासी ग्राम माडौर तहसील जवा जिला रीवा म०प्र०

==== गैरनिरामिकर्ता

2- शासन म०प्र०

निरामि विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील जवा राजस्व निरीक्षक मंडल डभौरा के प्रकृष्ट क्र० 22/अ-12/2015-16 आदेश दिनांक- 16-5-16

====  
 निरामि अन्तर्गत आरा- 50 म०प्र० भू-जो रा० सं० 1959 ई०.

====

मान्यवर,

निरामि के आधार सिद्धित है :-

1:- यह कि आर. निरामि न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि आराजी नं० 880/3 स्थित ग्राम माडौर तहसील जवा जिला रीवा का भूमिस्वामी निरामिकर्ता है। ए. सं. 882/2 व 885/2 म०प्र० शासन की भूमि है। आराजी नं० 880/3 में निरामिकर्ता का मकाम एवं कृप स्थित है, एवं उसी आराजी से लॉ 882/2 एवं 885/2 म०प्र० शासन की भूमि है, जिसे आदेश की बाड़ी एवं शौचालय अर्थात् पूर्व से स्थित है। एवं 882/1, व 885/1 पूर्व में म०प्र० शासन की भूमि थी जिसे भगवानदास साहू शुक्ला ने व्यवस्थापन करार अनादेश क्र०-01 को कृषि कर दिया था तब से उक्त आराजी पर सुमती का कब्जा दखल है। रजिस्ट्री में जो चौहदकी लिखाई गयी थी उसे विपरीत गैरनिरामिकर्ता क्र०-1 में जहाँ पर निरामिकर्ता का बाड़ी एवं शौचालय स्थित है

क्रमशः 2-पर

*(Signature)*

K

कुलकर्णी और कोर्ट  
 राजस्व मंडल म० प्र० वालियर  
 (सर्किट कोर्ट) रीवा  
 14-12-2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5527-II/16

जिला-रीवा

रामसुमिरन साहू/ श्रीमती सुगनी

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<p>1. आवेदक अधिवक्ता श्री अरुण कुमार साहू द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा, जिला रीवा के प्रकरण क्र० 22/अ12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.16 के विरुद्ध म०प्र० भू-रा० 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2. आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है, कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 14.12.16 को प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता द्वारा लगभग 7 माह के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता का धारा 05 के आवेदन में दर्शाये तथ्य समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण धारा 05 पर भी समाप्त किया जाता है।</p>	



  
सदस्य